आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 26.10.2024
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य के मामलों में ठोस पैरवी की आवश्यकता पर जोर दिया।
- स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
- उत्तरकाशी शहर में स्थिति सामान्य, जिले में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से ''मन की बात'' कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।

सीएम बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य के मामलों में ठोस पैरवी की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज देहरादून में न्याय विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है और इसके समग्र विकास के लिए सरकार को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने न्यायालयों से जुड़े मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए प्रशासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफॉरमेंस बेस्ड अप्रोच जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है, समस्याओं को कम करने और उनके समाधान की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उत्तरकाशी दौरा

स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी भ्रमण के दूसरे दिन जिले में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने गंगोत्री धाम में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बीच, उन्होंने हर्षिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर रावत ने शिक्षकों को विद्यालय में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल तैयार करने के निर्देश दिये, जिससे छात्रों का ज्ञानवर्धन हो और वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

अग्निवीर

अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा से चयनित करीब साढ़े छह सौ अग्निवीरों को छह माह के प्रशिक्षण के लिए देश भर के विभिन्न सेना प्रशिक्षण केंद्रों में भेजने की प्रक्रिया जारी है। अल्मोड़ा स्थित सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल आदित्य मिश्रा ने ये जानकारी दी। आकाशवाणी और दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर तक अग्निवीरों को देश की विभिन्न सेना बटालियनों में प्रशिक्षण के लिए भेजने की कार्यवाही की जाएगी। कर्नल मिश्रा ने बताया कि अग्निवीरों को दो नवंबर से छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आपदा प्राधिकरण की बैठक

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने चंपावत में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज जिला सभागार में आयोजित बैठक में श्री रुहेला ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का सरकारी मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जिले में विकास कार्यों के लिए करीब 200 करोड़ का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें जिले को स्मार्ट बनाने के लिए सभी जरूरी कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे।

उत्तरकाशी

उत्तरकाशी शहर में अब स्थिति सामान्य है। आज बाजार पूरी तरह खुले रहे। जिले में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू है। गौरतलब है कि 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में आयोजित आक्रोश रैली के दौरान बवाल हो गया था, जिसके बाद से उत्तरकाशी में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसके चलते व्यापारियों ने दो दिन बाजार बंद रखे।

''मन की बात''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से ''मन की बात'' कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कडी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा।

बस अड्डा

पौड़ी जिले में कोटद्वार परिवहन निगम का बस अड्डा अगले 16 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कोटद्वार रोडवेज बस अड्डे के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने सहायक महाप्रबंधक रोडवेज को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने रोडवेज बस स्टेशन के समीप सार्वजनिक शौचालय का भी निरीक्षण किया और निगम अधिकारियों को उसे साफ–सुथरा रखने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा विभाग

दिवाली पर्व पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा टीम का छापेमारी अभियान जारी है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने बागेश्वर जिले के गरुड़, कपकोट, रीमा और नगर क्षेत्र में बासी सामान नष्ट कराया। इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों और मॉल से घी, नमकीन, दाल, चीनी, मिठाई, मावा, तेल समेत 21 नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये। जिले के अभिहीत अधिकारी ललित मोहन पांडे ने विक्रेताओं को साफ और सुरक्षित मिठाइयां ही बेचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नमूने की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। श्री पांडे ने लोगों से भी कहा कि मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें, ताकि किसी भी तरह की मिलावट या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीजों से बचा जा सके।

संक्षिप्त समाचार–

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड– सीबीडीटी ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024–25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है।

उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का आदेश दिया है, जो दोपहिया सवारों के लिए गैर–अनुपालन वाले हेलमेट बेचते हैं। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये गए हैं।

इस साल अगस्त में कर्मचारी राज्य बीमा–ईएसआई योजना के अंतर्गत 20 लाख 74 हजार नए कर्मचारियों ने नामांकन कराया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार अगस्त में 28 हजार 9 सौ 17 नये प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के दायरे में लाया गया है। पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में साल दर साल पंजीकरण में 6 दशमलव आठ–जीरो प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने वन भूमि हस्तारण प्रकरणों के संबंध में वन विभाग और सड़क निर्माणदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों को 28 तारीख तक निस्तारण करने के निर्देश दिए।